



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2015/वैशाख 18, 1937

No. 121]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2015/VAISAKHA 18, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2015

**विषय : इंडोनेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्लेन मिडियम घनत्व के फाइबर बोर्ड जिनकी मोटाई 6 मिमी. या उससे अधिक हो" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।**

**फा. सं. 14/23/2014-डीजीएडी.**—यतः मै. ग्रिनप्लाई इंडस्ट्रीज लि. और मै. मंगलम टिम्बर प्रॉडक्ट्स लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है इंडोनेशिया और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्लेन मिडियम घनत्व के फाइबर बोर्ड जिनकी मोटाई 6 मिमी. या उससे अधिक हो (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या **"एमडीएफ"** भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है। आवेदकों ने जांच की शुरूआत करने के लिए आवश्यक संगत सूचना भी प्रस्तुत की है।

2. और यतः प्राधिकारी पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी,

मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

2. वर्तमान याचिका और प्रस्तावित जाँच में विचाराधीन उत्पाद “एमडीएफ” है। एमडीएफ को बाजार की भाषा में प्लेन एमडीएफ बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। प्लेन मिडियम घनत्व के फाइबर बोर्ड या प्लेन एमडीएफ बोर्ड एक संयोजित लकड़ी उत्पाद है जिसे लकड़ी के अपशिष्ट रेशे को यूरिया फारमेलिडाइड रेजिन या मेलामाइन रेजिन से एक साथ जोड़कर, ताप और दबाव द्वारा बनाया जाता है। इसकी समतल और एकसमान फिनिश के कारण इसका पार्टिशन, माड्यूलर फर्नीचर, कैबिनेट आदि में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

3. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ऊपर यथा परिभाषित एमडीएफ और उनके द्वारा उत्पादित और बेचा गया एमडीएफ में वास्तविक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के रूप में तुलनीय विशेषताएं हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं और इसलिए ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः नियमावली के अंतर्गत इस शब्द अर्थ के भीतर घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु के ‘समान वस्तु’ है।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के अध्याय 44 अर्थात् “लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं, लकड़ी का चारकोल” के अंतर्गत आता है और अधिक स्पष्ट रूप से शीर्ष 4411 के अंतर्गत “लकड़ी या अन्य लिग्निग्स सामग्री का फाइबर बोर्ड चाहे रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थों से जोड़ा गया हो अथवा नहीं” आता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से प्रस्तावित जांच और प्रस्तावित उपायों के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

### **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

5. यह याचिका मै. ग्रिनप्लाई इंडस्ट्रीज लि. और मै. मंगलम टिम्बर प्रॉडक्ट्स लि. द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन क्षमताओं वाली चार अन्य कंपनियां अर्थात् मै. रूशिल डेकोर लिमिटेड, मै. शिर्डी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. न्यूकेम लिमिटेड और मै. बालाजी एक्शन बिल्डवेल हैं। इन कंपनियों में से न्यूकेम लिमिटेड (जो न्यूवुड एमडीएफ ब्रांड को विनिर्माण करता है) 2010-11 के बाद से उत्पादन नहीं कर रहा है और बजाज इको-टेक प्राइवेट लिमिटेड ने आधार वर्ष से पहले उत्पादन बंद कर दिया है। रूशिल डेकोर लिमिटेड ने आवेदन के पक्ष में एक पत्र दिया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत उक्त सूचना के अनुसार आवेदकों का घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है।

6. यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने न तो विचाराधीन उत्पाद को आयात किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। अतः यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा और उनकी ओर से किया गया है और आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

### **ग. शामिल देश**

7. वर्तमान जांच में शामिल देश इंडोनेशिया और वियतनाम हैं।

### **सामान्य मूल्य**

8. निर्यात के देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमतों के किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और निर्यातक देशों के लिए विधिवत रूप से समायोजित भारत में विनिर्माण लागतों के अनुसार उत्पादन की परिकलित लागत जमा तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्यात के देशों में प्रत्येक उत्पाद प्रकार के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है। संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का परिकलित सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए परिवर्तन लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के तर्कसंगत अनुमान लगाए गए हैं। प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ इन अनुमानों को पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है।

**ड. निर्यात कीमत**

9. निर्यात कीमतों का अनुमान याचिकाकर्ता द्वारा जाँच अवधि के लिए आईवीआईएस आयात आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है जिसमें कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, दस्तावेज प्रभारों, क्लीनिंग प्रभारों आदि के लिए समायोजन किए हैं। आयात आंकड़े और समायोजन संबद्ध देशों से निर्यात कीमतों के अनुमान लगाने के लिए प्रथम दृष्टया तर्कसंगत प्रतीत होते हैं।

**च. पाटन मार्जिन**

10. प्राधिकारी के समक्ष आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु को अनुमानित सामान्य मूल्य भारत में निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों की तुलना की गई है, जिससे प्रथमदृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन धनात्मक और काफी अधिक है।

**छ. क्षति और कारणात्मक संबंध**

11. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण उनके मात्रा और कीमत प्रभावों की वजह से घरेलू उद्योग को संचयी रूप से क्षति हो रही है। अनिवार्य मापदंडों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि विभिन्न स्रोतों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति को देखते हुए क्षति का संचयी आकलन करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य और विभिन्न मापदंडों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है जिससे विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध होती है।

12. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो समग्र रूप से आयातों में वृद्धि, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में गिरावट, लाभों, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभों में कमी आदि की दृष्टि से हुई है। आवेदकों ने कम कीमत पर बिक्री के साक्ष्य के रूप में प्रतिकूल कीमत प्रभाव का भी दावा किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण आवेदक द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

**ज. जांच अवधि**

13. वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014 तक की है। तथापि क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल, 2011- मार्च 2012, अप्रैल, 2012- मार्च, 2013, अप्रैल, 2013- मार्च, 2014 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

**झ. जाँच की शुरुआत और आगे की प्रक्रिया**

14. उपर्युक्त के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य के मद्देनज़र, निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की जाँच करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी के लिए पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करते हैं।

**i. जांच अवधि**

15. वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि 1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014 (12 महीनों) तक की है। तथापि क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल, 2011- मार्च, 2012, अप्रैल, 2012- मार्च, 2013, अप्रैल, 2013- मार्च, 2014 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

**ii. सूचना प्रस्तुत करना**

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:—

**निर्दिष्ट प्राधिकारी  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग ,  
संसद मार्ग,  
नई दिल्ली- 110001**

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

**iii. समय-सीमा**

18. ऐसे सभी हितबद्ध पक्षकार जिनके पते उपलब्ध हैं, अपनी टिप्पणियां लिखित में एक पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि वह इस पत्र को जारी किए जाने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। यह सूचना मूल प्रति तथा साफ्ट प्रति दोनों में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**iv. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

19. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

क. गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

ख. अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

20. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां दो (2) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

21. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

25. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **v. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### **vi. असहयोग**

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

#### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2015

**Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning import of “Plain medium density Fibre Board having thickness of 6mm and above” originating in or exported from Indonesia and Vietnam.**

**F. No. 14/23/2014-DGAD.**—Whereas M/s. Greenply Industries Ltd. and M/s Mangalam Timber Products Ltd.(hereinafter referred to as ‘petitioner’ or “the applicant”) have filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of an Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6mm and above (hereinafter also referred to as the subject goods or “MDF”) originating in or exported from Indonesia and Vietnam (hereinafter also referred to as the subject countries). The applicants have provided relevant information necessary for initiation.

1. And whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the ‘dumping’ and ‘injury’ exists to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

#### **A. Product under consideration and Like Article**

2. The product under consideration in the present petition and proposed investigation is “MDF”. MDF is also known as Plain MDF Board in market parlance. Plain Medium Density Fibre Board or Plain MDF Board is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin, heat and pressure. It is widely used for partitions, Modular furniture, cabinets etc. due to its smooth and uniform finish.

3. The petitioners have claimed that the imported MDFs as defined above and the MDF produced and sold by them are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably and are therefore, technically and commercially substitutable. Therefore, the domestic products and imported subject goods are like products within the meaning of the term under the Rules

4. The product under consideration falls under the Chapter 44 of the Customs Tariff Classification, that is “wood and articles of wood; wood charcoal” and more specifically, under Heading 4411, “Fibre Board of Wood or other Ligneous Materials, Whether or not Bonded with resins or other Organic Substances”. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation and proposed measures.

**B. Domestic Industry & Standing**

5. The petition has been filed by M/s Greenply Industries Ltd. and M/s Mangalam Timber Products Ltd. Petitioners have submitted that there are four other companies with production capacities for the product under consideration in India, namely, M/s Rushil Décor Limited, M/s Shirdi Industries Limited, M/s Nuchem Limited and M/s Balaji Action Buildwell. Of these companies, Nuchem Limited (manufacturing NUWUD MDF brand) is not producing after 2010-11 and Bajaj Eco-Tec Products Limited ceased production prior to the base year. Rushil Décor Limited has given a letter of support in favour of the application. As per the above information submitted by the applicants, the applicants command a major proportion of the domestic industry.

6. It is also noted that petitioners have not imported the product under consideration, nor are they related to any importer or exporter of the product under consideration. Therefore, the application has been made by and on behalf of the domestic industry and the applicants satisfy the requirements of ‘standing’ under Rule 5 of the AD Rules and constitute ‘Domestic Industry’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

**C. Countries Involved**

7. The countries involved in the present investigation are Indonesia and Vietnam.

**D. Normal value**

8. In the absence of any direct evidence of selling prices of the subject goods in the domestic markets of the countries of exports, the domestic industry has estimated normal values of each product type in the countries of export based on constructed cost of production plus reasonable profit taking into account international raw material prices and manufacturing costs in India duly adjusted for the exporting countries. Reasonable estimates of the conversion cost, selling, general and administrative expenses have been made for arriving at the constructed normal value of subject goods in subject countries. The Authority has accepted these estimates as sufficient preliminary evidence for the purpose of initiation of the investigation.

**E. Export Price**

9. The export prices have been estimated based on the import data sourced by the petitioners for the period of investigation from IBIS data source after making adjustments on account of Ocean freight, Marine insurance, Document Charges, Cleaning Charges, etc. as per the best information available with them to arrive at ex-works export prices. The Import data and adjustments appear to be prima facie reasonable for estimation of the export prices from the subject countries.

**F. Dumping Margin**

10. As per the positive evidence placed by the applicants before the Authority the estimated Normal Values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices to India, indicating prima-facie that the subject goods are being dumped in the Indian market by exporters from the subject countries. The dumping margins so estimated, are positive and above *de minimis*.

**G. Injury and Causal Link**

11. The petitioners have alleged that dumped imports from the subject countries are cumulatively injuring the domestic industry due to the volume and price effects of dumped imports. Having examined the mandatory parameters, the Authority is of the view that cumulative assessment of injury is appropriate in view of the situation of competition between dumped imports from various sources and sales of the domestic industry. The petitioners have furnished information on volume and value of dumped imports from the subject countries and various parameters establishing injury to the domestic industry, on account of import of the product under consideration.

12. The petitioners have furnished evidence regarding injury suffered as a result of the alleged dumping of subject goods from subject countries in terms of increase in imports in absolute terms, decline in production, sales, capacity utilization, deterioration in profits, return on capital employed and cash profit etc. The applicants have also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports of subject goods from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

#### **H. Period of Investigation**

13. The period of investigation for the present investigation is from 1st October 2013 to 30th September 2014. However, the injury investigation period will cover the periods April 2011-March 2012, April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014 and the Period of Investigation (POI).

#### **I. Initiation of Investigation and further procedure**

14. In view of sufficient evidence of dumping, injury and causal links placed by the domestic industry as above, the Designated Authority, in terms of Rule 5 of the AD Rules, hereby initiates an anti-dumping investigation into the existence, degree of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and its effect on the domestic industry and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

##### **i. Period of Investigation**

15. The period of investigation for the present investigation is from 1st July 2013 to 30th June 2014 (12 months). However, the injury investigation period will cover the periods April 2011 to March 2012, April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014 and the Period of Investigation (POI).

##### **ii. Submission of information**

16. The exporters in subject countries, their government through their Embassies in India, the known importers and users in India would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

**The Designated Authority,  
Ministry of Commerce and Industry  
Department of Commerce  
Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties  
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street  
New Delhi-110001**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

##### **iii. Time limit**

18. All interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from date of publication of this notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

##### **iv. Submission of information on confidential basis**

19. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

20. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

21. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a ‘good cause’ statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

25. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**v. Inspection of Public File**

26. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**vi. Non-cooperation**

27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority